Reporters Required!
For
Delhi, Haryana, UP, Ludhiana, Shimla, Bihar, Jammu, Jaipur Amritsar, Bathinda,
Call/WhatsApp:
+91-9157875000
+91-9041488440
Email:
azadvaani65@gmail.com

Monthly Hindi/English Newspaper

Published from SAS Nagar (Mohali)

Azad वाणी

NEWS • VIEWS • ANALYSIS

RNI No.
PBBIL/26/A0779

Mon - 08 Jun - 2026 | Year - 01 | Issue - 63 | Page - 01 | Rs. - 5 | www.azadvaani.com

67,037 सरकारी नौकरियों का रिकॉर्ड: मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 355 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र, मेरिट आधारित भर्ती मॉडल को बताया पंजाब की नई पहचान

चंडीगढ़, 8 जून: पंजाब सरकार के रोजगार अभियान को नई मजबूती देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सोमवार को 355 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। इसके साथ ही मार्च 2022 में सरकार बनने के बाद राज्य में प्रदान की गई सरकारी नौकरियों की कुल संख्या 67,037 तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री ने इसे पंजाब में पारदर्शी और मेरिट आधारित भर्ती व्यवस्था की बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि अब सरकारी नौकरियां सिफारिश, रिश्वत या राजनीतिक प्रभाव से नहीं, बल्कि केवल योग्यता और कड़ी मेहनत के आधार पर मिल रही हैं।

नियुक्ति पत्र तकनीकी शिक्षा, सहकारिता, स्थानीय निकाय, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, पशुपालन, लोक निर्माण, आवास एवं शहरी विकास सहित विभिन्न विभागों में चयनित उम्मीदवारों को प्रदान किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार युवाओं को रोजगार देने के साथ-साथ उनके लिए ऐसे अवसर भी पैदा कर रही है, जिससे वे अपने ही राज्य में रहकर उज्ज्वल भविष्य बना सकें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने की घटनाओं ने युवाओं का भरोसा कमजोर किया है। वर्ष 2017 से देशभर में 93 पेपर लीक होने की बात सामने आई है, जबकि पंजाब में 2022 से अब तक एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यह ईमानदार और पारदर्शी शासन का परिणाम है।

भगवंत मान ने बताया कि सरकार ने शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में भी बड़े कदम उठाए हैं। राज्य में 25 नए आईटीआई बनाए जा रहे हैं और 13 मौजूदा संस्थानों को आधुनिक सुविधाओं से अपग्रेड किया जा रहा है। सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों के आधुनिकीकरण पर 20 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं, जबकि नंगल में 23 करोड़ रुपये की लागत से कैप्टन अमोल कालिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा सभी 91 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में सेमेस्टर इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिससे विद्यार्थियों को उद्योगों का व्यावहारिक अनुभव मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब आज शिक्षा के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। उन्होंने बताया कि राज्य में 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस स्थापित किए गए हैं, जहां विद्यार्थियों को एनईईटी, जेईई, क्लैट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की विशेष तैयारी करवाई जा रही है।

उन्होंने नव-नियुक्त कर्मचारियों से ईमानदारी और समर्पण के साथ जनता की सेवा करने का आह्वान किया तथा कहा कि सरकार का उद्देश्य युवाओं को विदेश जाने के लिए मजबूर होने से रोकना|

'मिशन क्लीन पंजाब' शुरू: अब रोज सुबह 7 से 8 बजे तक सड़कों पर उतरेंगे अधिकारी

चंडीगढ़, 8 जून: पंजाब में शहरी स्वच्छता व्यवस्था को नई दिशा देने के लिए स्थानीय निकाय मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सोमवार को तकनीक आधारित 'मिशन क्लीन पंजाब' की शुरुआत की। इस अनूठी पहल के तहत नगर निकायों के सभी अधिकारी प्रतिदिन सुबह 7 बजे से 8 बजे तक फील्ड में रहकर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करेंगे।

चंडीगढ़ स्थित विभागीय मुख्यालय से अभियान का शुभारंभ करते हुए मंत्री ने वीडियो कॉल के माध्यम से पहले दिन की गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि यह अभियान कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित मोबाइल ऐप, आकस्मिक निरीक्षण और साप्ताहिक प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से संचालित होगा। प्रत्येक शहरी निकाय क्षेत्र को 10 किलोमीटर के जोनों में बांटा गया है, जिनकी जिम्मेदारी एडीसी, नगर निगम कमिश्नर, संयुक्त कमिश्नर और कार्यकारी अधिकारियों को सौंपी गई है।

हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि यह कोई एक दिन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि गंदगी के खिलाफ रोजाना चलने वाला अभियान है।

शिक्षा विभाग के कर्मचारी संगठनों से मिले वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा

चंडीगढ़, 8 जून: पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सोमवार को शिक्षा विभाग के विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत बैठकें कर उनकी समस्याओं और मांगों पर चर्चा की। कर्मचारी शिकायतों के समाधान के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने पांच अलग-अलग यूनियनों के प्रतिनिधियों को धैर्यपूर्वक सुना और उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया।

वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार कर्मचारियों के कल्याण और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। बैठकों के दौरान शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न मांगों की वर्तमान स्थिति और उन पर की जा रही कार्रवाई की जानकारी दी।

अमृतसर पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय हथियार तस्करी और हवाला नेटवर्क का किया भंडाफोड़, अफगान नागरिक समेत 4 गिरफ्तार

चंडीगढ़/अमृतसर, 8 जून: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के अभियान के तहत अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए अंतरराष्ट्रीय अवैध हथियार तस्करी और हवाला नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक अफगान नागरिक सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से आठ अत्याधुनिक पिस्तौल और सात जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अफगानिस्तान निवासी एवं वर्तमान में पुणे में रह रहे इस्माइलखेल तौहीद, तरनतारन के मंगजीत सिंह और शमशेर सिंह तथा अमृतसर के गुरलाल सिंह के रूप में हुई है। बरामद हथियारों में एक .30 बोर बेरेटा, चार 9 एमएम ग्लॉक और तीन .30 बोर पिस्तौल शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों का एक्टिवा स्कूटर भी जब्त किया है।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया
कि जांच में सामने आया है कि आरोपी विदेश में बैठे तस्करों के संपर्क में थे, जो गुप्त स्थानों के जरिए हथियारों की खेप भेजते थे। ये हथियार आगे अपराधियों तक पहंचाए जाने थे।

पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पहले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बाद की जांच में गुरलाल सिंह और फिर हवाला नेटवर्क संचालित करने वाले अफगान नागरिक इस्माइलखेल तौहीद को भी गिरफ्तार किया गया। तौहीद सूखे मेवों के कारोबार की आड़ में हवाला लेन-देन संचालित कर रहा था।

पुलिस इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों और विदेशी कड़ियों की पहचान के लिए जांच जारी रखे हुए है। मामले में अमृतसर के थाना इस्लामाबाद और थाना गेट हकीमा में शस्त्र अधिनियम के तहत दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं।

13 करोड़ की सिंचाई परियोजनाओं का शुभारंभ

चंडीगढ़/अमरगढ़/मालेरकोटला, 8 जून: पंजाब सरकार ने किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने और भूजल पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए अमरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में करीब 13 करोड़ रुपये की सिंचाई परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। पंजाब के जल संसाधन एवं भूमि एवं जल संरक्षण मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने गांव माणकमाजरा और दहलीज़ खुर्द में इन परियोजनाओं की शुरुआत की। इस अवसर पर अमरगढ़ के विधायक प्रो. जसवंत सिंह गज्जनमाजरा भी मौजूद रहे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र की 3,832 एकड़ से अधिक कृषि योग्य भूमि को पहली बार नहरी पानी की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार हर खेत तक नहरी पानी पहुंचाने और किसानों को स्थायी सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य नहरी पानी की प्रत्येक बूंद को खेतों के अंतिम छोर तक पहुंचाकर भूजल, पंजाब के प्राकृतिक संसाधनों और कृषि व्यवस्था को सुरक्षित करना है।

18 माह का प्रशिक्षण पूरा करने वाले 33 पटवारियों को मिले नियुक्ति पत्र

चंडीगढ़, 8 जून: पंजाब सरकार ने राजस्व विभाग को और अधिक मजबूत एवं जनहितैषी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 33 पटवारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। पंजाब के राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने पंजाब भवन में आयोजित समारोह के दौरान इन नव-नियुक्त पटवारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए और उन्हें जनता की सेवा पूरी ईमानदारी, निष्ठा और पारदर्शिता के साथ करने का आह्वान किया।

इस अवसर पर मंत्री ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का संदेश साझा करते हुए कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पटवारी राजस्व प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं और आम लोगों के साथ उनका सीधा संपर्क रहता है।

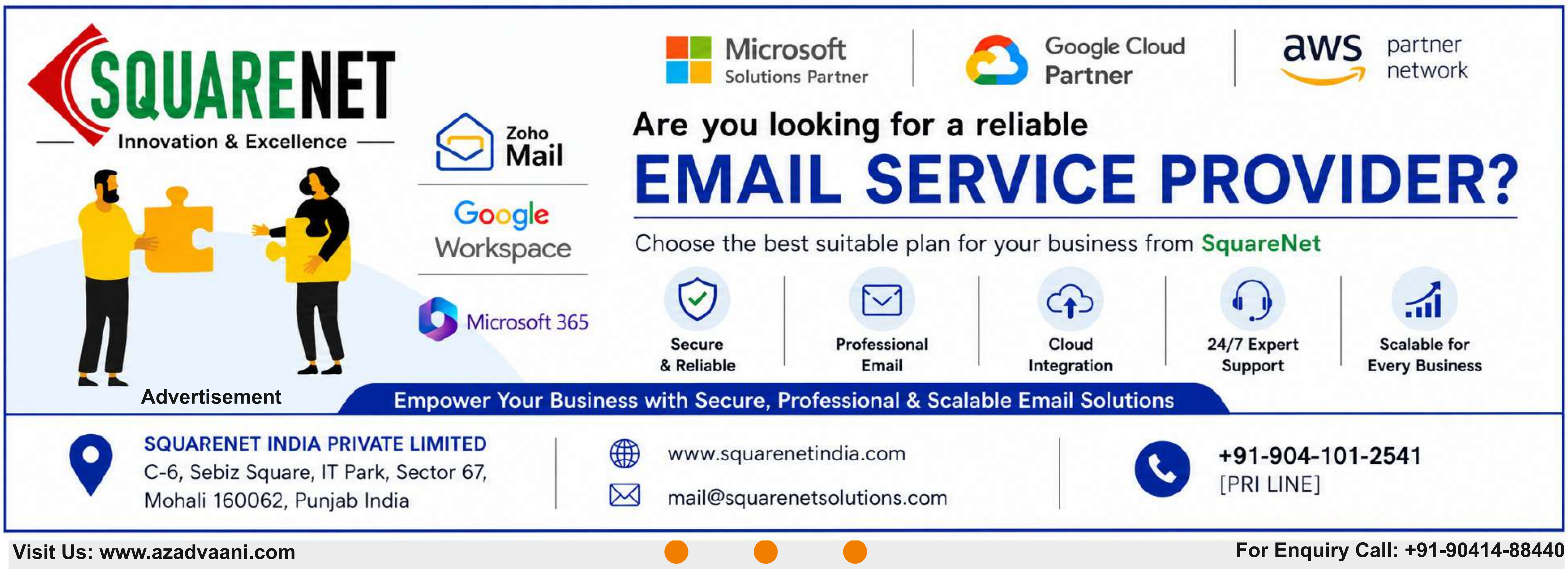

विशेष मतदाता पुनरीक्षण की तैयारियां तेज, 25 जून से शुरू होगा घर-घर सत्यापन अभियान

चंडीगढ़, 8 जून: पंजाब में विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन-एसआईआर) प्रक्रिया को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने सोमवार को राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों को एसआईआर अभियान की प्रक्रियाओं, दिशानिर्देशों और जिम्मेदारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए पंजाब की मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अनिंदिता मित्रा ने बताया कि राज्यभर में एसआईआर के तहत घर-घर गणना और सत्यापन चरण 25 जून 2026 से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया को सुचारू ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्धारित नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों की पूरी जानकारी होना बेहद आवश्यक है। इससे जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को बेहतर प्रशिक्षण दिया जा सकेगा और मतदाता पुनरीक्षण कार्य बिना किसी परेशानी के पूरा किया जा सकेगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों को समन्वय के साथ कार्य करना होगा ताकि किसी भी मतदाता या कर्मचारी को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। उन्होंने जोर देकर कहा कि मतदाता सूची लोकतंत्र की बुनियाद है और इसकी शुद्धता सुनिश्चित करना निर्वाचन तंत्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

श्रीमती अनिंदिता मित्रा ने राज्य के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) और ईआरओ को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करें। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान बीएलओ और अन्य फील्ड कर्मचारियों की सभी शंकाओं और प्रश्नों का समाधान किया जाना चाहिए, ताकि वे पूरी समझ और आत्मविश्वास के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें। उन्होंने कहा कि जितना बेहतर प्रशिक्षण होगा, एसआईआर प्रक्रिया उतनी ही प्रभावी और सुचारू होगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया कि पंजाब की सभी राजनीतिक पार्टियों को विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के बारे में जानकारी दे दी गई है और उनसे इस प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न कराने में सहयोग करने की अपील की गई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम गलती से मतदाता सूची से न हटे और साथ ही किसी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल न होने पाए। उन्होंने कहा कि पारदर्शी, सटीक और अद्यतन मतदाता सूची तैयार करना ही इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया और अधिक मजबूत हो सके।

आर्ट थेरेपी से बदल रही नशा पीड़ितों की जिंदगी: 'युद्ध नशेयां विरुद्ध' अभियान के तहत पंजाब के 15 जिलों में मिल रहा नया जीवन

चंडीगढ़, 8 जून: पंजाब सरकार की महत्वाकांक्षी मुहिम 'युद्ध नशेयां विरुद्ध' के तहत नशे के खिलाफ चल रही लड़ाई अब केवल इलाज और दवाओं तक सीमित नहीं रह गई है। राज्य के 15 जिलों में संचालित 30 सरकारी नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्रों में आर्ट थेरेपी (कला आधारित उपचार) नशे की लत से जूझ रहे लोगों के पुनर्वास का प्रभावी माध्यम बनकर उभर रही है। रंगों, चित्रकारी, स्केचिंग और हस्तकला जैसी रचनात्मक गतिविधियां मरीजों को अपनी भावनाएं व्यक्त करने, मानसिक तनाव कम करने और जीवन में नई उम्मीद जगाने में मदद कर रही हैं।

पंजाब सरकार द्वारा लीडरशिप इन मेंटल हेल्थ प्रोग्राम (एलएमएचपी) के सहयोग से शुरू की गई इस पहल के तहत नशा मुक्ति केंद्रों में चिकित्सा उपचार और काउंसलिंग के साथ-साथ कला आधारित गतिविधियों को भी शामिल किया गया है। यह भारत की पहली ऐसी फेलोशिप आधारित पहल मानी जा रही है, जिसका उद्देश्य नशे के दुष्प्रभावों को कम करना और मरीजों के मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाना है। इन केंद्रों में भर्ती मरीज हर सप्ताह निर्धारित समय पर पेंटिंग, रंग भरने, स्केचिंग और अन्य रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेते हैं। उनकी कलाकृतियों में अक्सर उनके संघर्ष, पारिवारिक यादें, सपने और सामान्य जीवन में लौटने की इच्छाएं झलकती हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि नशे की लत से जूझ रहे लोगों के इलाज में सबसे बड़ी चुनौती उन्हें अपनी भावनाएं और मानसिक पीड़ा व्यक्त करने के लिए प्रेरित करना होती है। आर्ट थेरेपी इस दूरी को कम करने में बेहद प्रभावी साबित हो रही है। अमृतसर स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज के स्वामी विवेकानंद नशा मुक्ति केंद्र की काउंसलर भावना शर्मा के अनुसार, जब मरीज केंद्र में आते हैं तो वे अक्सर चिंता और अवसाद से घिरे होते हैं तथा अपनी भावनाएं साझा करने में कठिनाई महसूस करते हैं। लेकिन आर्ट थेरेपी सत्रों के दौरान वे रंगों और चित्रों के माध्यम से अपनी बात व्यक्त करना शुरू कर देते हैं। इससे उन्हें अपनी भावनाओं को समझने और नशा-मुक्त जीवन की ओर सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद मिलती है।

कर्मचारियों की जायज़ मांगों का होगा समाधान

चंडीगढ़, 8 जून: पंजाब सरकार ने कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान और उनके कल्याण को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए शिक्षा विभाग की विभिन्न कर्मचारी यूनियनों के साथ व्यापक संवाद शुरू किया है। इसी कड़ी में पंजाब के वित्त मंत्री एवं कर्मचारी शिकायतों के निपटारे के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी के अध्यक्ष हरपाल सिंह चीमा ने सोमवार को शिक्षा विभाग की पांच प्रमुख यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ अलग-अलग बैठकों का आयोजन किया। बैठकों का उद्देश्य कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों को विस्तार से सुनना तथा उनके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाना था।

पंजाब सिविल सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में आयोजित इन बैठकों के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार संवाद और सहमति के माध्यम से कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और उनकी जायज़ मांगों को अनदेखा नहीं किया जाएगा।

बैठकों में शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न यूनियनों द्वारा उठाए गए मुद्दों की वर्तमान प्रशासनिक स्थिति तथा उन पर चल रही कार्रवाई की जानकारी दी। विभागीय प्रस्तुतिकरण की समीक्षा करने के बाद हरपाल सिंह चीमा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कर्मचारियों की लंबित और वैध मांगों के समाधान के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तेजी लाई जाए, ताकि संबंधित कर्मचारियों को जल्द राहत मिल सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए सकारात्मक और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपना रही है।

'गैंगस्टरां ते वार' के 139वें दिन 263 गिरफ्तार, नशा विरोधी अभियान में 81 तस्कर दबोचे

चंडीगढ़, 8 जून: पंजाब को अपराध और गैंगस्टर संस्कृति से मुक्त बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान 'गैंगस्टरां ते वार' के 139वें दिन पंजाब पुलिस ने व्यापक कार्रवाई करते हुए प्रदेश भर में 469 चिन्हित स्थानों पर छापेमारी की और 263 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान एक हथियार भी बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार 20 जनवरी 2026 को शुरू किए गए इस विशेष अभियान के तहत अब तक कुल 35,076 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

पंजाब पुलिस द्वारा जारी जानकारी के अनुसार ये छापेमारियां गैंगस्टरों और उनके सहयोगियों से जुड़े उन स्थानों पर की गईं जिन्हें पहले से चिन्हित और मैप किया गया था। यह अभियान पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव के नेतृत्व में एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) और जिला पुलिस इकाइयों के समन्वय से लगातार चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य राज्य में सक्रिय आपराधिक नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करना और कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाना है।

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 69 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियातन कार्रवाई भी की, जबकि 24 लोगों को पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया। इसके अलावा दो फरार अपराधियों (प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स) को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभियान के तहत गैंगस्टरों के नेटवर्क, उनके सहयोगियों और आपराधिक गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है।

पंजाब पुलिस ने आम जनता से भी सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 पर गुप्त रूप से गैंगस्टरों, वांछित अपराधियों और अन्य आपराधिक गतिविधियों की सूचना दे सकते हैं। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

पंजाब पुलिस ने आम जनता से भी सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 पर गुप्त रूप से गैंगस्टरों, वांछित अपराधियों और अन्य आपराधिक गतिविधियों की सूचना दे सकते हैं।

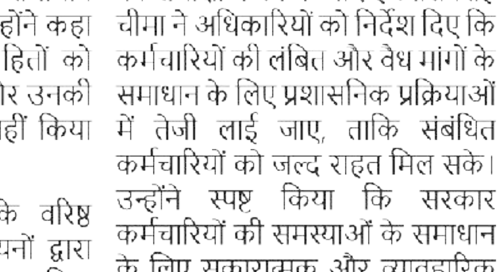

नशा-मुक्त पंजाब के लिए 42.95 करोड़ रुपये की कार्य योजना तैयार, डॉ. बलजीत कौर ने बहु-विभागीय रणनीति को दी अंतिम रूपरेखा

चंडीगढ़, 8 जून: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने नशा-मुक्त, स्वस्थ और प्रगतिशील पंजाब के निर्माण के अपने संकल्प को और मजबूत करते हुए वर्ष 2026-27 के लिए नशों के उन्मूलन और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी व्यापक राज्य कार्य योजनाओं को अंतिम रूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसी उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने पंजाब भवन, चंडीगढ़ में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक के दौरान नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन (NAPDDR) तथा नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीज़न्स के तहत वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित राज्य कार्य योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक में गृह विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आयुष, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, युवा सेवाएं एवं खेल, सूचना एवं जनसंपर्क, पंजाब स्किल डेवलपमेंट मिशन, जेल विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार नशे की समस्या से निपटने के लिए केवल कानून प्रवर्तन पर निर्भर नहीं है, बल्कि रोकथाम, जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक पुनर्स्थापन को शामिल करते हुए एक व्यापक और परिणामोन्मुख रणनीति पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि नशों के खिलाफ लड़ाई को जन आंदोलन का रूप देने के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी आवश्यक है।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिए नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन के तहत 42.95 करोड़ रुपये की राज्य कार्य योजना प्रस्तावित की गई है। इस राशि का उपयोग नशा विरोधी जागरूकता अभियानों, जीवन कौशल शिक्षा, परामर्श सेवाओं, नशा मुक्ति एवं पुनर्वास कार्यक्रमों, क्षमता निर्माण गतिविधियों तथा समुदाय आधारित हस्तक्षेपों के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशों से दूर रखने के लिए स्कूलों, कॉलेजों और गांव-शहर स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि सरकार खेलों, सांस्कृतिक गतिविधियों और युवा सहभागिता को बढ़ावा देकर युवाओं को सकारात्मक दिशा में प्रेरित करने के लिए भी विशेष प्रयास कर रही है। इसके साथ ही शिक्षकों, काउंसलरों, स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस अधिकारियों और अन्य फ्रंटलाइन कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि वे नशे से संबंधित चुनौतियों की पहचान और समाधान में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकें। पुनर्वास संबंधी योजनाओं पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि नशा प्रभावित व्यक्तियों के लिए परामर्श, उपचार, पुनर्वास, कौशल विकास और रोजगार प्रशिक्षण के अवसरों का विस्तार किया जाएगा।

herbegy™

Think pure think herbal

PREMIUM SPICES RANGE

Pure Spice. Rich Flavour.

PURE | AROMATIC | PREMIUM QUALITY

Advertisement

For Dealer Inquiry Contact:

727-515-0015

Printed by: Desh Sewak Printers Limited, Sector-29-D, Chandigarh – 160030 and Published by: Shafiur Rahman from #2111 SF, TDI City, Sector-110, Mohali, Sahibzada Ajit Singh Nagar, Punjab – 140307. Owner, Publisher & Chief Editor: Shafiur Rahman. Title Verification Number: PBBIL/26/A0779. Periodicity: Monthly.